

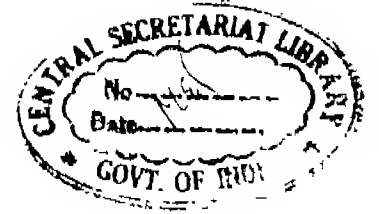


# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खंड—I  
PART I—Section—I

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 208 ]  
No. 208 ]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 10, 1996/अग्रहायण 19, 1918  
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 10, 1996/AGRAHAYANA 19, 1918

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1996

सं. 16-2/92-बाग. प्रशा.—कृषि में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर राष्ट्रीय समिति का मूल गठन रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग के अधीन 1981 में किया गया था। इस समिति का पुनर्गठन 1986, 1989 और पुनः 1993 में किया गया। कृषि में प्लास्टिक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये इस समिति को और अधिक प्रभावी बनाने तथा उसके प्रयासों को और अधिक समन्वित रूप से केन्द्रित करने के लिये कृषि में प्लास्टिक के उपयोग पर राष्ट्रीय समिति (अब के बाद इसे समिति कहा जायेगा) को कृषि और सहकारिता विभाग के अधीन पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया है:—

- |   |          |
|---|----------|
| 1. केन्द्रीय कृषि मंत्री                            | —अध्यक्ष |
| 2. सचिव,<br>कृषि और सहकारिता विभाग                  | —सदस्य   |
| 3. महानिदेशक<br>भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद          | —सदस्य   |
| 4. अपर सचिव (प्रभारी)<br>कृषि और सहकारिता विभाग     | —सदस्य   |
| 5. कृषि आयुक्त,<br>कृषि और सहकारिता विभाग           | —सदस्य   |
| 6. उप महा निदेशक (इंजी.),<br>कृषि और सहकारिता विभाग | —सदस्य   |
| 7. सलाहकार (कृषि),<br>योजना आयोग                    | —सदस्य   |
| 8. अपर सचिव,<br>जल संसाधन मंत्रालय                  | —सदस्य   |

- |  |             |
|--|-------------|
| 9. विसीय सलाहकार,<br>कृषि और सहकारिता विभाग  | —सदस्य      |
| 10. कृषि उत्पादन आयुक्त, कर्नाटक सरकार   | —सदस्य      |
| 11. कृषि उत्पादन आयुक्त, महाराष्ट्र सरकार  | —सदस्य      |
| 12. कुलपति,<br>इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय,<br>रायपुर।   | —सदस्य      |
| 13. परियोजना निदेशक,<br>जल प्रौद्योगिकी केन्द्र<br>भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद।                           | —सदस्य      |
| 14. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,<br>भारतीय पैट्रो रसायन लि.,<br>बड़ोदरा।                                  | —सदस्य      |
| 15. नाबार्ड का प्रतिनिधि   | —सदस्य      |
| 16. अध्यक्ष,<br>ट्रिप मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन  | —सदस्य      |
| 17. श्री अब्दुल हय,<br>गांव व पो.आ. रायरे बांका, चाया केयोटी रेनवे,<br>थाना बिस्फी, जिला मधुबनी (बिहार)। | —सदस्य      |
| 18. श्री के. कनमने पोटिके,<br>616 तिरुवल्लुवर, कुदियिरुप्पु,<br>अन्ना नगर, पश्चिम मद्रास-600 040.        | —सदस्य      |
| 19. बागवानी आयुक्त,<br>कृषि और सहकारिता विभाग  | —सदस्य सचिव |

2. इस समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:—

- (1) उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को अनुकूलतम बनाने के विशेष संदर्भ में कृषि की उत्पादकता बढ़ाने, उत्पाद की क्वालिटी सुधारने और कटाई उपरांत हानि को कम करने के लिये कृषि में प्लास्टिक्स के उपयोग के लिये योजनाएं तैयार करना,
- (2) कृषि में प्लास्टिक्स के उपयोग को बढ़ाने के लिए राजस्व नीति, राज-सहायता, किसानों के लिए सहायता आदि जैसे उपयुक्त नीतिगत उपाय करना।
- (3) टपका सिंचाई पद्धतियां हरे-गृहों, मलिंग, पैकेजिंग आदि के विशेष संदर्भ में प्लास्टिक से बनी विभिन्न वस्तुओं के उपयोग को अधिकाधिक प्रचारित करने और अपनाने के लिये कार्य नीतियां सुझाना।
- (4) कृषि, जल प्रबन्ध आदि में प्रयुक्त प्लास्टिक्स के लिये क्वालिटी संबंधी मानक निर्धारित करने हेतु सहायतार्थ डाटा बेस तैयार करने के वास्ते अनुसंधान और विकास के संवर्धन की व्यवस्था करना।
- (5) प्लास्टिक संवर्धन (प्लास्टिकल्चर) जिला कार्यक्रम और विशेषकर प्लास्टिक संवर्धन विकास केन्द्रों और सामान्य रूप से प्लास्टिक संवर्धन केन्द्रों के समग्र विकास के कार्यान्वयन का प्रभावशाली ढंग से पर्यवेक्षण और प्रबोधन करना।
- (6) देश में प्लास्टिक के संवर्धन से संबंधित कोई भी अन्य विषय।

3. प्रारंभ में, समिति का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिये होगा। गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर होगा। समिति की आवश्यकता होने पर अक्सर लेकिन साल में कम से कम दो बार बैठक होगी। समिति वार्षिक आधार पर सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

4. समिति के लिये अपेक्षित सचिवालयी सहायता इंडियन पैट्रो केमिकल्स लिमिटेड से लिये गये कार्मिकों से युक्त केन्द्रीय समन्वयन सेल द्वारा दी जाती रहेगी।

5. समिति के कार्यों के लिये की गई यात्राओं के संबंध में कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्तों/महंगाई भत्तों के व्यय पूर्ति समिति को दिये गये धन में से की जायेगी। अन्य पदेन सदस्यों के संबंध में तदनुकूपी व्यय का वहन उनके संबंधित विभागों द्वारा किया जायेगा।

6. सरकार, यदि आवश्यकता हो तो, समिति की संरचना और विचारार्थ विषयों, आदि में उचित परिवर्तन कर सकती है।

### आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों, लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय तथा भारत सरकार के अन्य संबंधित मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि आम सूचना के लिये इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

डा. जी. एल. कौल, बागवानी आयुक्त

## MINISTRY OF AGRICULTURE (Department of Agriculture and Cooperation) RESOLUTION

New Delhi, the 18th November, 1996

**No. 16-2/92-HA.**—The National Committee on Use of Plastics in Agriculture (NCPA) was originally set up under the Department of Chemicals & Petrochemicals in 1981. The Committee was reconstituted in 1986, 1989 and again in 1993. In order to make this committee more effective and to focus its endeavours in a more coordinated manner for promoting the use of plastics in agriculture, it has been decided to reconstitute the National Committee on Use of Plastics in Agriculture (herein after referred to as the committee) under the Department of agriculture & Cooperation, as under:—

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Union Agriculture Minister  | — Chairman. |
| 2. Secretary,<br>Deptt. of Agriculture & Cooperation                                       | — Member.   |
| 3. Director General,<br>Indian Council of Agriculture Research.                            | — Member.   |
| 4. Additional Secretary (Incharge),<br>Deptt. of Agriculture & Cooperation.                | — Member.   |
| 5. Agriculture Commissioner,<br>Department of Agriculture & Cooperation                    | — Member.   |
| 6. Dy. Director General (Engg.)<br>Indian Council of Agriculture Research                  | — Member.   |
| 7. Adviser (Agri.),<br>Planning Commission.  | — Member.   |
| 8. Additional Secretary,<br>Ministry of Water Resources.                                   | — Member.   |
| 9. Financial Adviser,<br>Deptt. of Agriculture & Cooperation.                              | — Member.   |
| 10. Agriculture Production Commissioner,<br>Government of Karnataka.                       | — Member.   |
| 11. Agriculture Production Commissioner,<br>Government of Maharashtra.                     | — Member.   |
| 12. Vice-Chancellor,<br>Indira Gandhi Krishi Vishwa Vidyalaya, Raipur,                     | — Member.   |
| 13. Project Director,<br>Water Technology Centre,<br>Indian Agriculture Research Institute | — Member.   |
| 14. Chairman & Managing Director,<br>Indian Petrochemicals Limited, Vadodra.               | — Member.   |
| 15. Representative of NABARD.  | — Member.   |
| 16. President,<br>Drip Manufacturers Association   | — Member.   |

17. Shri Abdul Hai,  
Vill. & P.O.  
Kaire Banka, Via Keoti Ranway,  
P.S Bisfi, Distt. Madhubani,  
Bihar. — Member.
18. Shri K. Ranmane Portke,  
616, Thiruvalluvar,  
Kudiyiruppu, Anna Nagar West,  
Madras-600 040 — Member
19. Horticulture Commissioner,  
Deptt. of Agriculture & Cooperation. — Member Secretary.
2. The terms of reference of the committee would be as under:
- (i) to prepare plans for use of plastics in agriculture with a view to increase agricultural productivity with special reference to optimising the use of available water resources, improving quality of the product, and reducing post harvest losses.
  - (ii) To recommend suitable policy measures such as fiscal policy subsidy, assistance to farmers etc. for promotion of use of plastics in agriculture.
  - (iii) To suggest strategies for propagation and increased adoption of various plasticulture applications with special reference to drip irrigation systems, green houses, mulching, packaging, etc.
  - (iv) To arrange promotion of Research and Development to build data base, to assist in prescribing quality standards for plastics used in agriculture, water management etc.
  - (v) To supervise and monitor effectively the performance of Plasticulture Development Centres (PDCs) in particular and overall development of plasticulture in general.
  - (vi) Any other matter connected with promotion of plasticulture in the country.

3. The term of the Committee will initially be for a period of three years from the date of issue of this Resolution. The non-official members shall hold office during the pleasure of the Chairman. The Committee shall meet as often as necessary but at least once in a year. The Committee shall submit its reports to the Government on annual basis.

4. The Secretarial assistance required for the Committee will continue to be provided by the Central Coordination Cell consisting of personnel drawn from the Indian Petrochemicals Ltd. as at present.

5. The expenditure on TA/DA of the Vice-Chancellors of Agricultural Universities and the non-official members in connection with the journeys undertaken on Committee's business will be met out of the funds allocated for the committee. The corresponding expenditure in respect of other ex-officio members will be borne by their respective Department.

6. The Government may make suitable changes in the composition and the terms of reference, etc. of the committee if required.

### ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territories Administrations, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats and the concerned Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Dr. G. L. KAUL, Horticulture Commissioner

प्रतिस्पर्धा की स्थिति की पुनर्स्थापना करना है न कि किसी निश्चित स्रोत से आयात को रोकना।

(5) एल सी एफ सी और एच सी एफ सी के मूल्यों के अन्तर के बारे में किया गया दावा गलत और वर्तमान कार्यवाहियों के संदर्भ में असंगत है। तथापि, प्राधिकारी ने एच सी एफ सी के बारे में कोई व्यापक जांच नहीं की है, क्योंकि यह उत्पाद वर्तमान जांच के दायरे से बाहर है।

(6) एल सी एफ सी की मांग में, यदि कोई गिरावट आई है तो उसकी ध्यान में रखते हुए क्षमता उपयोग के सामान्य स्तर पर उचित बिक्री मूल्य पर विचार किया गया है।

(7) एल सी एफ सी की वर्तमान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कीमतें वर्तमान जांच के लिए असंगत हैं और इसलिए इस बारे में दिए गए तर्क रद्द किए जाते हैं।

(8) यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने 66.1% कार्बन तत्व वाले एल सी एफ सी के लिए सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और उचित बिक्री मूल्य निकाला है और कार्बन की भिन्नता को नजर अंदाज कर दिया गया है।

(9) पूर्व वृत्तान्त को छोड़कर प्राधिकारी प्रारम्भिक जांच परिणामों के पैरा 19 से 26 की पुष्टि करते हैं।

#### अन्तिम जांच-परिणाम

33. उपर्युक्त बातों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि :

- (1) रूस तथा कजाकिस्तान मूल के अथवा यहां से भारत को किया गया एल सी एफ सी का निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया;
- (2) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है;
- (3) घरेलू उद्योग को यह हानि रूस और कजाकिस्तान मूल के अथवा यहां से किए गए निर्यात के कारण हुई है।

34. इसलिए, प्राधिकारी प्रारम्भिक जांच-परिणामों के पैरा 47 से 49 की पुष्टि करते हैं और रूस और कजाकिस्तान मूल के अथवा यहां से किए गए एल सी एफ सी के सभी आयातों पर नीचे बताई गई दरों पर अंतिम प्रति-पाटन शुल्क लगाने का सुझाव देते हैं :

निर्यातक का नाम	शुल्क की राशि (रु. प्रति मी. टन)
1. मूल देश : रूस	
डेरक रफेल एण्ड कं., लंदन	10900
नोरकोलोयूज एस ए, लक्सम्बर्ग	17400
नोरकोलोयूज एल पी, न्यूयार्क	18600
सोसायेटे एनोनाइन डेस मिनरल्स, लक्सम्बर्ग	12300
सीनक्रीट बीबी, रोटर्डम	16900
उपरोक्त के अलावा निर्यात	18600
2. मूल देश : कजाकिस्तान	
सोसायेटे एनोनाइन डेस मिनरल्स लक्सम्बर्ग	18500
उपरोक्त के अलावा निर्यातक	18500

35. प्राधिकारी उपर्युक्त बातों के अध्याधीन 23-5-96 को अधिसूचित प्रारम्भिक जांच-परिणामों की पुष्टि करते हैं।

दीपक चटर्जी, प्राधिकृत अधिकारी

## MINISTRY OF COMMERCE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 1996

### FINAL FINDINGS

**Subject :** Anti-dumping investigation concerning imports of Low Carbon Ferro Chrome (LCFC) originating in or exported from Russia and Kazakhstan—Final Findings.

**47/ADD/94.**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof.

### PROCEDURE

2. The Procedure described below has been followed:

- (i) The Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) notified Preliminary Findings vide Notification No. 47/ADD/94 dated the 23rd May, 1996 and requested the interested parties to make their views known in writing within forty days from the date of its publication;
- (ii) Forwarding a copy of the Preliminary Findings, all known interested parties were requested to furnish their views, if any, on the preliminary findings within forty days of the date of the letter;
- (iii) The Authority also forwarded a copy of the Preliminary Findings to the Embassy of Russia and Kazakhstan in New Delhi with a request that the exporters and other interested parties may be advised to furnish views on the Preliminary Findings;
- (iv) The Authority has concluded the investigation within the extended time limit allowed by the Central Government.
- (v) The Authority held a public hearing on 11-10-96 to hear views orally. All the parties attending the public hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally. The parties were advised to collect copy of the views expressed by the opposing parties and were requested to offer their rebuttals, latest by 24-10-96.
- (vi) In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to all known interested parties and comments received on the same have also been duly considered in these findings.

### PETITIONER'S VIEWS

3. The petitioner in response to the Preliminary Findings made the following submissions :

- (i) Zimbabwe has been rightly adopted as a surrogate country. Even countries such as Brazil and European Union facing similar problems adopted Zimbabwe as surrogate country and imposed anti dumping duty.



- (ii) The Authority should consider factors prevailing during period of investigation and the latest prices of LCFC are not relevant. It may also be possible that the exporters have temporarily raised the prices to give the impression that they are not dumping.
- (iii) The custom duty has been reduced from 50% at the time of filing petition to 27% at present. If the same is considered the landed cost of the material stands further reduced.
- (iv) The amount of Anti-dumping Duty recommended by the Authority is substantially and significantly less than what such rate should have been, particularly in case of M/s. Derek Raphel and Co. Ltd., London and M/s. Societe Anonym Des Mi. Luxembourg.
- (v) It appears that the fair selling price adopted by the Authority is less than the fair selling price submitted by the petitioner. The rate of Anti-dumping Duty in case of the two exporters mentioned in the above para is lower by about Rs. 8000/-.

#### VIEW OF EXPORTERS, IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES

4. The importers and exporters have expressed their views, and the same are briefly mentioned below :

##### (a) Exporters :

- (i) M/s. SYNCRET replied that it was impossible to provide the information requested by the Authority in Rs. since rate of exchange kept on changing and was rather unstable. The questionnaire sent by the Authority did not give exporters fair chance to respond.
- (ii) The contention of the petitioner that the information with regard to Normal Value was not available is unacceptable. Russian Ministry of Metallurgy published the price of LCFC on a monthly basis for 1993 and 1994
- (iii) Russia can hardly be compared with Zimbabwe for constructing cost of production.
- (iv) Para 10 of Preliminary Findings is inconclusive, as the Normal Value stated is without unit of measurement and carbon content.
- (v) LCFC imported in India had a carbon content between 0.15% and 0.25%. Both the grades are not produced by the petitioner.
- (vi) Since the prevailing market prices are much higher than the period of investigation, the whole issue is irrelevant.

##### (b) Importers and Other Interested Parties :

- (i) The Authority has not completed the investigation within the time limit prescribed under the Rules, including the extended time period.
- (ii) Cost of Production worked out by the Authority for the purpose of Normal Value is highly doubtful as

the details of cost have not been made available. During the period of investigation the imports were cheaper, but subsequently the prices have increased. The international prices move so fast and scenario changes so rapidly that conditions necessitating dumping also disappear.

- (iii) There is a substantial price difference in LCFC depending upon the carbon content in the ferro alloy. The Authority should classify carbon content while calculating Normal Value.
- (iv) The imports of LCFC have shown significant increase because of almost negligible imports in the preceding years. The Steel industry faced recession resulting in decline in production. The decline in production in case of petitioner is almost equivalent to the decline in production of stainless steel for which LCFC is used.
- (v) A large number of consumers have changed technology resulting in decline in demand for LCFC.
- (vi) Comparison of the prices of HCFC and LCFC are not irrelevant for the purposes of the investigation as observed by the Authority in the Preliminary Findings. The price difference between the two in the international market is Rs. 19/- per kg. compared to Rs. 40/- per kg. in case of India.
- (vii) The imposition of Anti-dumping Duty would benefit only the monopoly producer.
- (viii) While disclosing the essential facts in terms of rule 16 supra, the Authority has not disclosed the data on which the cost of production is based. They have also desired to know the Normal Value and the injury margin. It has been contended that the information sought by them would be necessary for them to submit a reply.

#### EXAMINATION BY AUTHORITY

5 The submissions made by the petitioner, exporters, importers and other interested parties have been examined and considered by the Authority while arriving at these findings and, wherever appropriate, have been dealt hereinafter. The comments made subsequent to the disclosure of the essential facts have also been appropriately dealt with hereinafter.

6. The Authority confirms, in the absence of any direct response from the exporters in the form and manner prescribed, having made these findings on the basis of the facts available to it as per rule 6(8) supra.

#### LIKE ARTICLES AND DOMESTIC INDUSTRY

7. Under Rule 2(d) "like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such an article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation.